no response from the Government. Let them have a dialogue with the leaders....(*Interruptions*).

SHRI NILOTPAL BASU: Let the Government respond. (*Interruptions*).

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI (Uttar Pradesh): Discussion has been going on at different levels. (*Interruptions*).

SHRI J. CHITHARANJAN (Kerala): What steps has the Government taken to settle this matter? (*Interruptions*). I request the Prime Minister to make a statement. (*Interruptions*). What steps is the Government taking to settle this issue? (*Interruptions*).

श्री नरेश यादव (बिहार): आखिर सरकार क्या कर रही है इस बारे में....(**व्यवधान**)

श्रीमती कमला सिन्हा (बिहार): कर्मचारियों की हड़ताल से पूरे देश को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है....(**व्यवधान**) सारे देशवासी कठिनाई में हैं....(**व्यवधान**)

SHRI NILOTPAL BASU: Will the Government negotiate with them or not? (*Interruptions*). We would like to know whether the Government will negotiate or not. (*Interruptions*).

श्री दीपांकर मुखर्जी (पश्चिमी बंगाल): यह चिट्ठी की बात है, चिट्ठी, चिट्ठी)। एक चिट्ठी के लिए चक्कर हो रहा है...(**व्यवधान**)

श्री नीलोत्पल बसु: इसके चलते तो सरकार भी जा सकती है....(**व्यवधान**)

SHRI NILOTPAL BASU: I would like to know whether the Government will negotiate or not. The entire postal activities have come to a standstill. It is not a small thing... (*Interruptions*)

श्रीमती कमला सिन्हा: प्रधान मंत्री जी को कुछ इस पर भी कमेंट करने को बोलिए।...(**व्यवधान**)

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): सभापति जी, सरकार और डाक कर्मचारियों के बीच में वार्ता चल रही थी। यह ठीक है कि कर्मचारियों ने जो रवैया अपनाया था वह समझौते में सहायक नहीं था। लेकिन सरकार समझौता करना चाहती थी। अभी भी बातचीत चल रही है और कोई न कोई रास्ता निकलेगा, ऐसा मैं इस सदन को आश्वासन देना चाहता हूं।

DISCUSSION ON THE WORKING OF THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS *contd.*

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहार वाजपेयी): सभापति महोदय, विदेश मंत्रालय पर हुई लम्बी बहस का उत्तर सचमुच में इस बात का परिचायक है कि माननीय सदस्य विदेश मंत्रालय से सम्बन्धित देश की सुरक्षा से जुड़े हुए सवालों में बड़ी रूचि लेते हैं। यह स्वाभाविक भी है और यह आवश्यक भी है। हमारे देश में विदेश नीति पर हमेशा एक आम सहमति रही है। इसका अर्थ यह नहीं है कि समय-समय पर कुछ मतभेद नहीं उभरे लेकिन भारत की विदेश नीति स्वतंत्र हो, स्वावलम्बन को बढ़ावा दें, भारत के हितों की रक्षा करने में समर्थ हो और विश्व के शांति स्थापन में योगदान दे, यह प्रारम्भ से विदेश नीति का लक्ष्य रहा है। इसको लेकर एक आम सहमति रही है। जब यह कहा जाता है कि आम सहमति टूट गई है तो मेरा निवेदन है कि स्थिति के साथ सही न्याय नहीं किया जाता। हमारी विदेश नीति के अन्तर्गत सभी पड़ौसियों के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने की बात है, यह सम्बन्ध अभी तक स्थापित रहे हैं। जब से इस सरकार ने कार्यभार संभाला है इन संबंधों को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़े हैं। हमारे राष्ट्रपति जी अभी नेपाल की सफल यात्रा करके आए हैं। बंगला देश की प्रधान मंत्री थोड़े दिन पहले दिल्ली में आई थीं और उनसे बड़े मैत्रीपूर्ण वातावरण में, सहयोग के वातावरण में चर्चा हुई। मालदीव्स के राष्ट्रपति भी आए थे। वह सार्क सम्मलेन के अभी तक अध्यक्ष रहे हैं। अब कोलम्बो में वह दूसरे को कार्यभार सौंपेंगे। उनसे भी बड़ी अंतरंग बातचीत हुई। हमारे विदेश सचिव अभी बंगला देश गए थे, वह भूटान की यात्रा भी करके आए हैं। तो यह कहना कि भारत अलग-थलग पड़ गया है, यह न्याय करना नहीं है। हां, पाकिस्तान के साथ हमारी समस्याएं हैं। हमारी तरफ से लगातार यह कोशिश होती रही है कि पाकिस्तान के साथ संबंध सामान्य हों और सामान्य संबंध मैत्रीपूर्ण संबंधों में बदलें, आर्थिक सहयोग के लिए नए दरवाज़े खुलें, लोगों के आने-जाने में आसानी हो लेकिन इस संबंध में पाकिस्तान से जितना सहयोग मिलना चाहिए था, नहीं मिला है। पाकिस्तान से वार्ता चल रही थी जब पुरानी सरकार थी। ढाका में एक फार्मूला भी तैयार हुआ था जिसके अनुसार बातचीत का क्रम तय होना था लेकिन सात-आठ महीने पाकिस्तान ने अपनी सहमति नहीं दी। इसके साथ ही देश के भीतर ऐसी विरोधी गतिविधियां बढ़ाने का प्रयास हुआ जिनसे कानून और व्यवस्था की स्थिति को खतरा पैदा हो।

जम्मू-कश्मीर जो आज शांत है जहां चुनाव हुए हैं, लोगों ने इच्छा से अपने प्रतिनिधि निर्वाचित किए हैं, विधान सभा काम कर रही है, यात्री बड़ी संख्या में जा रहे हैं, पर्यटक भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लेकिन एक आशंका का वातावरण बनाने का प्रयास किया गया है। यहां कहा जा रहा है कि इस-भूखण्ड में तनाव है। कहां तनाव है? हम तो तनाव नहीं चाहते। सीमा पर गोलीबारी होती है, पहले से भी होती रही है। कुछ प्रश्न हैं जो अनिर्णीत पड़े हैं, उन्हें बातचीत के द्वारा ही हल किया जा सकता है। भारत और पाकिस्तान को साथ-साथ रहना है। हम पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। मित्रों में परिवर्तन कर सकते हैं, विरोधियों की संख्या भी घटा सकते हैं लेकिन पड़ोसी हैं, जैसा है, हम और वे अच्छे पड़ोसी के रूप में रहें, इस बात का हमेशा प्रयास हुआ है। यह प्रयास जारी रहेगा। मैंने पाकिस्तान के प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखा था, उन्हें निमंत्रण दिया कि हमारी आपकी मुलाकात होनी चाहिए। कोलम्बो में मुलाकात होगी और फिर बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाएगा, यह मैं आशा करता हूं। शिमला समझौते के अंतर्गत सभी समस्याएं द्विपक्षीय तरीके से हल होनी हैं, किसी की मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है। जो सद्भावना के कारण कुछ भूमिका अदा करना चाहते हैं, उनके हम आभारी हैं लेकिन अपनी समस्याओं से हम स्वयं जूझेंगे और अपने पड़ोसी के साथ द्विपक्षीय संबंध के आधार पर उन समस्याओं का समाधान निकालेंगे। सभापति महोदय, आप केयरो गए थे जी-15 की बैठक में भाग लेने के लिए आप के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल गया था। उस बैठक में कहीं भारत को अलग-थगल किया जाए, यह वातावरण नहीं था। गुटनिरपेक्ष देशों का सम्मेलन हुआ, काफी प्रयास किए गए कि भारत का नाम लेकर प्रथम विस्फोट करने के लिए भारत की निन्दा की जाए, लेकिन इसे समर्थन नहीं मिला है। यह गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की परम्परा के खिलाफ भी था इस तरह की मांग करना। हम वहां द्विपक्षीय मामलों पर विचार नहीं करते हैं। भारत जैसे देश को, इतने प्राचीन और विशाल देश को जिसकी जनसंख्या 100 करोड़ है और जिसमें अपरिमित क्षमताएं हैं, 50 वर्ष की हमारी उपलब्धियां हैं और विश्व इस बात को समझ रहा है। दो-तीन महीने पहले जो स्थिति थी उस में परिवर्तन है। हमने पोखरण—दो में जो कुछ किया वह सुरक्षा की आशंकाओं को देखते हुए किया और सुरक्षा के बारे में हमारी आशंकाएं हैं, यह वे भी स्वीकार करने लगे हैं जो हमारे अणु-परीक्षण के कट्टर विरोधी हैं। लेकिन यह पहला अवसर नहीं है जब ऐसा हुआ। जब भारत ने एनपीटी पर दस्तखत करने के लिए मना किया था उस समय सारी दुनिया जैसे हमारे खिलाफ उमड़ पड़ी थी। भारत की कठोरतम आलोचना हुई थी लेकिन भारत ने कहा कि हमारे लिए सिद्धान्त का सवाल है, हम भेदभावमूलक संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे और उस समय जो सदन में सदस्यों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की थी पोखरण के प्रथम विस्फोट के बाद, देश में जैसा वातावरण बना था, सभापति महोदय, उस समय आप भी सदन के सदस्य थे और आपने भी चर्चा में भाग लिया था और आपने 1974 के विस्फोट के बारे में कहा था:

> "I personally feel a halting decision has been taken. We should have done it much earlier. But let us not say about UP elections, the President's rule..."

यह आरोप लगाए गए थे कि 1974 का अणु-परीक्षण क्यों किया गया। क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, क्योंकि सरकार के सामने और भी कठिनाइयां हैं और उनका उत्तर देते हुए यह बात बड़े बलपूर्वक ढंग से कही गई थी:

> "We should have done it much earlier. But let us not say about UP elections, the President's Rule... This shows the diseased mind of the Opposition people as to how a good thing done by our scientists and by the Government, they want to lower it down."

इतिहास अपने को दोहरा रहा है, पूरी मात्रा में नहीं तो कुछ अंशों में दोहरा रहा है। जो उस समय सत्ता में थे वे प्रतिपक्ष में हैं, जो उस समय प्रतिपक्ष में थे वे सत्ता में हैं। लेकिन देश की सुरक्षा के बुनियादी सवाल बदलती हुई राजनीति पर निर्भर नहीं रह सकते, न निर्भर रहना चाहिए।

इस चर्चा में भी यह प्रश्न उठाया गया था और यह कहा गया था कि हमारा प्रचार जितना प्रभावशाली होना चाहिए उतना नहीं है। उसमें कमियां हैं, मैं मानता हूं। जो हमारे दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं वे हमारा विरोध करते हैं लेकिन जो सहमत भी हैं वे भी इतना साहस नहीं जुटा पाते कि सार्वजनिक रूप से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। आर्थिक शक्ति इसमें अपना खेल खेलती है। प्रचार की कमी की शिकायत श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने में भी हुई थी। सदन में बहस का जवाब देते हुए उन्होंने कहा था, मैं उद्धृत कर रहा हूं:

> "And any incident or information that comes to the knowledge of

hon. Members of Parliament will always be useful to us in seeing how these services and Missions can be improved. But, when we talk of publicity abroad or of the image of India which our Missions are projecting, let us remember that we are dealing with sovereign independent States who have their own assessment of their national interests. They are not concerned with our national interests; they are concerned with what picture suits them and that is the picture which is normally projected in that country. Our task, therefore, is to seek their co-operation in matters where our interests converge as they do with many countries and to seek adjustment and accommodation wherever there are divergencies."

फिर इंदिरा जी ने अपने भाषण में एक बात और कही थी, मैं उसका उल्लेख करना चाहूंगा:

"We hope that country will now present a picture of unity and not of division; of progress and not of stagnation; of purposeful activity and not or meaningless presumptions. All this will condition and influence our external relations and what others think of us."

अगर हम स्वयं ही आत्म निन्दा के शिकार हो जाएंगे, अगर हम स्वयं ही अपने वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और टेक्नीशियन्स की उपलब्धि को सही रूप में नहीं आंकेंगे तो फिर दुनिया में आलोचना हो और हरेक देश अपने हित के हिसाब से आचरण करता है तो उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता।

सभापति जी, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आलोचना नहीं होनी चाहिए। सरकार की कमियां, सरकार की खामियां यदि आलोचना का विषय हैं तो होनी चाहिए। हम भी आलोचना करते रहे हैं। लेकिन देश के जीवन में एक ऐसा नाजुक मोड़ आता है जिसमें अगर देश एकता की तस्वीर प्रस्तुत नहीं कर सकता तो हमारे राष्ट्रीय हितों पर आंच आती है। मैं कुछ पुराने भाषण देख रहा था। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जो इस समय लंदन में इलाज के लिए हैं, उन्होंने वहां बी०बी०सी० को एक भेंट दी थी और उसमें उन्होंने कहा था कि परमाणु परीक्षण को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए, वैज्ञानिकों की कद्र होनी चाहिए। पहले पोखरण के समय वी०पी० सिंह की क्या प्रतिक्रिया थी, इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है।

"Deputy Speaker, Sir, if anything had been exploded by the Pokhran explosion, then it has been the myth that vital technology can be the exclusive possession of a few countries, it has been unsettled to some who had envisaged a world order on these premises. They throw up their hands in horror and accuse us of opening the nuclear Pandora's box and turn pale at the thought of a puny little country, the little eleven with no sense of responsibility, will follow the lead of the tramp called India and start the entire dirty job of producing nuclear bombs, a job which was the sole monopoly of the nuclear weapon countries. What a pious thought!" वी० पी० सिंह के शब्दों का यहां उल्लेख कर रहा हूं। "I wish it had occured before the push button was released to drop the nuclear bombs on Hiroshima and Nagasaki. The high priests who had installed the nuclear deity on the high pedistal of their global relations are now scared that some of their worshippers may build their own temples. Let it be known that if any country does build a nuclear bomb, it will be following the example of Hiroshima and not that of Pokhran."

ये शब्द आज भी कितने सत्य हैं। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हमारे आलोचक हैं। हमारे उनसे मतभेद हैं। लेकिन लंदन में रोग शैय्या पर पड़े हुए उनकी प्रतिक्रिया सचमुच में एक राष्ट्रवादी की प्रतिक्रिया है। फिर हम तो यह स्पष्ट कर चुके हैं और इसको लगातार स्पष्ट करते रहेंगे कि हमने जो कुछ किया है अपनी सिक्योरिटी कन्सर्न को ध्यान में रखकर किया है। किसी के खिलाफ हमने कदम नहीं उठाया। सारा वातावरण पिछले तीन दशकों से बिगड़ा है। भारत की जिस दिशा में हम देखें ऐटमी हथियार हैं। हमारी तैयारी तो अपने प्रयत्नों से, अपने प्रयोगों से, अपने उपकरणों से, अपने वैज्ञानिकों से है लेकिन इधर उधर से हेराफेरी का सामान लेकर जिन्होंने हथियार जोड़ने में सफलता पायी है

उनके इरादों को हमें समझना पड़ेगा। जहां तक चीन का संबंध है, चीन के साथ हम अपने संबंधों को सामान्य बनाना चाहते हैं और सचमुच में संबंध सामान्य है भी।

श्री जार्ज फर्नांडीज़ के जिस वक्तव्य की बड़ी चर्चा की जाती है, उसका स्पष्टीकरण वे दे चुके हैं। यह बात अलग है कि स्पष्टीकरण प्रमुखता से नहीं छपा और जो वक्तव्य उन्होंने दिया नहीं था वह बड़ी प्रमुखता से छप गया। जब चीन के नेताओं से हमारी बात होती है तो वह बातचीत खुल कर होती है और होनी भी चाहिये। लेकिन सार्वजनिक रूप से अपने मतभेदों को प्रकट करना, यह आवश्यक नहीं है। बरसों बाद चीन के साथ मुठभेड़ के पश्चात् जब देश में जनता सरकार थी तो उसके विदेश मंत्री के नाते कई साल बाद मैंने चीन की यात्रा की थी और उस यात्रा के बाद श्री नरसिंह राव और राजीव गांधी ने जिन समझौतों की पुष्टि की, उन्हें विस्तृत रूप दिया, व्यापक रूप दिया, उनकी नींव उस समय रखी गई थी कि सीमा पर पीस और ट्रैंक्विलिटी रहेगी और सीमा पर शान्ति है, स्थिरता है। लेकिन हम चाहते हैं कि सीमा के बारे में जो चर्चा चल रही है, उसमें गति आए, प्रश्न हल होते जाएं। देखें, इसके संबंध में क्या प्रतिक्रिया हमें मिलती है?

सभापति महोदय, सरकार ने आर्थिक प्रतिबन्धों के विरूद्ध देश को तैयार करने का प्रयास किया है। मैं इस सुझाव से सहमत हूं कि इस संबंध में प्रतिपक्ष के साथ लगातार विचार-विनिमय होना चाहिये, चर्चा होनी चाहिये। इसमें कोई बाधा नहीं है। हमारी तरफ से कोई कठिनाई नहीं है। पोखरण के बाद बातचीत हुई भी थी। हम तो पोखरण के पहले प्रतिपक्ष के नेता को इसके बारे में सूचना देना चाहते थे लेकिन वह उपलब्ध नहीं थे। बाद में चर्चा हुई तो यह बात संतोष के साथ ग्रहण की गई कि इतने बड़े पैमाने पर प्रतिपक्ष को साथ लेने का प्रयास पहले नहीं हुआ था। मैं पहले भी कह चुका हूं, इस बात को मैं दोहराना नहीं चाहता हूं कि 1974 में मैं प्रतिपक्ष में था और अच्छा सदस्य था। हमें तो पोखरण के बारे में भनक भी नहीं पड़ी। हमने शिकायत नहीं की क्योंकि हम जानते थे कि ऐसा नाजुक मामला है कि यह सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं बन सकता। इस स्थिति को समझने की जरूरत है।

मैं आर्थिक प्रश्नों की चर्चा कर रहा था। जो भी प्रतिबंध लगाए गए हैं वे प्रतिबंध किस सीमा तक परिणाम पैदा करेंगे, यह कहना मुश्किल है। डालरों की संख्या में उनका जोड़ लगाना मुश्किल है। कल प्रणब बाबू ने इस बात का उल्लेख किया था। लेकिन मोटे तौर पर यह बात स्पष्ट हो गयी है कि जो सहायता हमें मिल रही थी और मानवीय कार्यों के लिए मिल रही थी उसमें कोई बाधा पैदा नहीं होगी। जो पाइप लाइन में है, वह प्राप्त होगा।

एनरान की तरफ से महाराष्ट्र की सरकार को इस बारे में किसी तरह की सूचना नहीं दी गयी है। उनका प्रयास होगा वे अन्य बैंकों से संबंध स्थापित करें। उनकी जिम्मेदारी है कि जो समझौता हुआ है उसके अनुसार वे प्रकल्प को पूरा करें।

जिन्होंने प्रतिबंध लगाए हैं अब उन्हीं देशों में बहस हो रही है कि प्रतिबंध लगाना ठीक है या नहीं और नुकसान ज्यादा किसको होता है, जिसके विरुद्ध प्रतिबंध लगाए गए हैं या जिसने प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें हम कोई संतोष अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन इस तरह की सैंक्शन्स आनी प्रोडक्टिव हैं, यह समझ में आ रहा है। अगर थोड़ी-बहुत कठिनाई होती है तो उसे सहने के लिए देश तैयार है और देश तैयार होना चाहिए और इस काम में हमें आपका सहयोग प्राप्त होगा, इसका भी मुझे पूरा विश्वास है।

प्रतिबंध लगे हैं। वे देश के विरुद्ध लगे हैं। जनता को उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। देश में क्षमता, शक्ति है और इसलिए हम स्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार है। जहां तक कि विवरण का सवाल है तो मैं प्रतिपक्ष के साथ बातचीत के लिए तैयार हूं। आपको विश्वास में लेने के लिए तैयार हूं और आपकी सलाह और आपके परामर्श के अनुसार इस तरह की भविष्य में रणनीति बनायी जाए, इसके अनुसार भी सरकार चलने के लिए तैयार है। कठिनाई तब होती है जब राष्ट्र हित के ऊपर अन्य हितों को रखा जाता है। थोड़ी-बहुत राजनीति मैं समझ सकता हूं। लेकिन विश्व में भारत की बिखरी हुई तस्वीर जाए तो हम देश के साथ न्याय नहीं करेंगे।

सभापति महोदय, चर्चा में अनेक मुद्दे उठाए गए थे। सी०टी०बी०टी० के बारे में लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या भारत सी०टी०बी०टी० को स्वीकार करेगा और हम से कहा जा रहा है कि हम बिना शर्त स्वीकार कर लें और तत्काल स्वीकार कर लें। यह हमें मंजूर नहीं है। हमने घोषणा कर दी है कि हम आगे परीक्षण नहीं करेंगे। मोरिटोरियम लगा दिया है। मेरिटोरियम को हम डी जुरे कानून का रूप देने की तैयारी कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि बड़े देश, जिनके पास एटमी हथियारों के ढेर लगे हैं, वे इस बात पर विचार करेंगे। सचमुच में वक्त आ गया है जब भारत और पाकिस्तान मिल कर, क्योंकि अब दोनों अणु शस्त्रों से सम्पन्न देश है, एक तो आपस में यह समझौता करें कि इन हथियारों का पहले प्रयोग करने वाले वे नहीं होंगे और फिर दूसरे, दोनों मिल कर विश्व के एटमी देशों से कहें कि आप इन हथियारों को समाप्त करने का एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाइये। ये हथियारों के अंबार क्यों लगाए जा रहे हैं? ये

किसके खिलाफ लगाए जा रहे हैं? देश को इस बारे में अपना मन बनाना पड़ेगा। दुनिया को इस वर्तमान विकृति की व्यवस्था को अस्वीकार करना होगा। हम चाहते हैं पूर्ण एटमी निःशस्त्रीकरण। श्री राजीव गांधी ने इस संबंध में एक बड़ी योजना यूनाइटेड नेशंस में प्रस्तुत की थी। उसके साथ किसी संकट का सामना करने के लिए हम तैयार रहें, यह भी तैयारी होती रही थी। इसीलिए मैं यह कह रहा हूं कि पोखरण दो के सवाल पर देश में आम सहमति टूट गई, यह कहना ठीक नहीं होगा। हम ऑप्शन खुला रखें, इस पर तो सारा देश एकमत था, हम भी उसमें शामिल थे, लेकिन हमारे आस-पास क्या हो रहा है, यह जब हमने देखा और किस तरह से प्रक्षेपास्त्र बनाए जा रहे हैं, चुनौतियां दी जा रही हैं तो हमें लगा कि अब वह ऑप्शन को एक्सरसाइज़ करने का अवसर आ गया है। कठिनाइयां होंगी, हम जानते थे, लेकिन राजनीतिक दल एक सही रवैया अपनायेंगे, विशेषकर वे जिनके हाथों में सत्ता रही है, इसकी हमें आशा थी। ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी ने अब मांग की है और यह कहा है कि: Congress criticized the BJP Government for not doing enough to weaponise the nuclear programme. वेपनाइजेशन की बात हो रही है। हमारे ऊपर दबाव है कि हम वेपनाइजेशन न करें, हमारे ऊपर दबाव है कि हम मिसाइल्स के मामले में और जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, उन्हें स्वीकार कर ले। यह स्थिति हमें मंजूर नहीं है आत्म-रक्षा के लिए और हम एक स्वतंत्र सर्व-प्रभुतासंपन्न देश हैं जो पचास साल संकटों में से निकला है। वह देश ऐसे किसी सशर्त समझौते को स्वीकार नहीं करेगा। हम सी॰टी॰बी॰टी॰ पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। जेनेवा में आणविक निरस्त्रीकरण की दिशा में जो कदम हो रहे हैं, उन को भी हम प्रोत्साहन देने के लिए तैयार है, उन में भाग लेने के लिए तैयार हैं। हमारी तरफ से एक दृष्टिकोण, एक रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। किसी को उस में दुर्बलता की गंध नहीं आनी चाहिए और न पराक्रमशूरता का एहसास मिलना चाहिए। सुरक्षा से जुड़े हुए मामले गंभीर मामले हैं और उनका फैसला शांति के साथ करने की आवश्यकता है।

सभापति जी, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इतनी लंबी चर्चा में भाग लेकर अपने सुझावों से हमें लाभांवित किया। मैं सारे भाषण तो नहीं सुन सका, लेकिन मैंने उन का संक्षिप्त रूप देखा है और मुझे लगता है कि कुछ वक्ताओं को छोड़कर इस बार आलोचना रचनात्मक ज्यादा थी, सहयोगात्मक ज्यादा थी। हम इस का संतोषजनक प्रत्युत्तर देंगे। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि आम-सहमति पर देश की विदेश नीति को और देश की कूटनीति को प्रभावशाली ढंग से चलाने का काम यह सरकार करती रहेगी और इस कार्य में हमें सदन की सद्भावना प्राप्त होगी। यह आशा मैं व्यक्त करके समाप्त करना चाहता हूं।

MR. CHAIRMAN: I adjourn the House till 2.30 p.m.

The House then adjourned for lunch at fifty-four minutes past twelve of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-five minutes past two of the clock,

The Vice-Chairman (Shri John F. Fernandes) *in the Chair.*

The Vice-Chairman (Shri John F. Fernandes): Shri Raj Nath Singh—absent.

THE HIGH COURT OF MADRAS (ESTABLISHMENT OF A PERMANENT BENCH AT MADURAI BILL 1997

SHRI R. MARGABANDU (Tamil Nadu): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the establishment of a permanent Bench of the High Court of Madras at Madurai.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI R. MARGABANDU: Sir, I introduce the Bill.

THE SUPREME COURT OF INDIA (ESTABLISHMENT OF A PERMANENT BENCH AT CHENNAI) BILL, 1997

SHRI R. MARGABANDU (Tamil Nadu): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the establishment of a permament Bench of the Supreme Court at Chennai.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI R. MARGABANDU: Sir, I introduce the Bill.